



2026:AHC:69190

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 5464 वर्ष 2026

हरेंद्र सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रभात कुमार पांडे, रंजीत दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन को 10.02.2020 की आरोप पत्र, 15.02.2020 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ केस अपराध संख्या-413 वर्ष 2019 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या-74 वर्ष 2020 (राज्य बनाम अजीत बाइंड और अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो एसीजेएम, न्यायालय संख्या-2, जौनपुर की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा केवल उसे परेशान करने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि जैसा कि कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया गया है, उसके द्वारा कभी भी नहीं किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक से जो भी कथित वसूली की गई है, वह घटना के लगभग दो महीने बाद हुई है और कथित घटना से इसकी तत्काल कोई प्रासंगिकता नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना की पुष्टि करने के लिए आवेदक के खिलाफ शायद ही कोई सबूत है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष जांच किए बिना, संबंधित विवेचनाधिकारी ने आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद अपने न्यायिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिमाग को लागू किए बिना, संबंधित अदालत ने उक्त आरोप पत्र पर अपराध का संज्ञान लिया जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस तरह, इसे रद्द किया जा सकता है।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता, जो आवेदक की ओर से उठाए जाने की मांग की गई है, तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित होगी, और इसमें साक्ष्य की मूल्यांकन शामिल होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संज्ञान लेते समय, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए और संबंधित अदालत से लघु विचारण आयोजित करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

5. पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि संज्ञान/सम्मन लेने के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल अभिलेखों पर सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय दर्ज करने की आवश्यकता होती है, और उससे मिनी विचारण करने या अभियुक्त के बचाव की जांच करने की उम्मीद नहीं की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एसडब्ल्यू पलानिटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; (2002) 1 एस.सी.सी. 241**, यह माना गया था कि जिस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" है और क्या "दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार" है। **नूपुर तलवार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में; (2012) 11 एस.सी.सी. 465**, यह दोहराया गया था कि जारी करने की प्रक्रिया के चरण में सामग्री पर विचार करने का सीमित उद्देश्य परीक्षण के दौरान उत्पादित वास्तविक साक्ष्य से अलग होने के नाते, चरण में लागू किया जाने वाला परीक्षण यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई सामग्री "आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त" थी और "अपराध को साबित करने और स्थापित करने के लिए पर्याप्त" नहीं थी। संज्ञान लेने के चरण में, एक अदालत का प्राथमिक ध्यान यह निर्धारित करना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, जिसका अर्थ है कि क्या यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अपराध किया गया है, न कि मामले या सबूत के गुणों में तल्लीन करने के लिए।



6. अनुच्छेद 227 संख्या-3254 वर्ष 2024 (कैलाश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के तहत मामलों में पारित दिनांक 6.5.2024 के निर्णय में इस न्यायालय के हाल के निर्णय में उपरोक्त कानूनी स्थिति पर भी विचार किया गया है।

7. प्राथमिकी में किए गए कथन, आरोप पत्र, जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों और मामले के तथ्यों को देखने के रूप में अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। बार में किए गए सभी प्रस्तुतीकरण, तथ्य के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

8. उपरोक्त कारणों से, प्रस्तुत आवेदन योग्यता से रहित है और इसलिए, इसे **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश आवेदक को कानून के अनुसार उपलब्ध अन्य सभी कानूनी उपायों का लाभ उठाने से नहीं रोकेगा।

मार्च 31, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)